

‘ना वेतन-भत्ते का आदेश निकाला, ना दर्जा दिया, फिर विपक्ष क्यों मुद्दा बना रहा है’

मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद के बीच बोले अशोक गहलोत

जयपुर, (का.प्र.)। हाल ही में छह विधायकों के मुख्यमंत्री सलाहकार पद पर नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद के बीच सीएम अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि हमने इस नियुक्ति के लिए अलग से वेतन भत्ते या सुविधाओं को लेकर कोई आदेश नहीं निकाला लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे कोई जुम कर दिया हो। राज्य मंत्री बनाए गए राजेंद्र गुप्ता के अब तक पद न संभालने पर गहलोत ने कहा कि मैं और पीसीसी अध्यक्ष उनसे बात करूँगे और कोई रास्ता निकाल लेंगे।

■ **महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को हजारों कांग्रेस जन जायेंगे दिल्ली रैली में**

■ **उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के बेरोजगारों को लेकर कहा “भाजपा इनको भड़का रही है”**

जिम्मेदार बताया।

पीसीसी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को संघवाद के खिलाफ बताते हुए कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण ही आज राज्य कमजोर हो रहे हैं। गहलोत ने कहा पांच राज्यों में चुनाव हैं, इस वजह से कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम अब रोजाना नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो यह काम आगे भी जारी रह सकता है। गहलोत ने यह भी कहा कि अब तक एक्ससाइज ड्यूटी का पैसा सभी राज्यों के हिस्से में आता था, उसमें भी केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्यों को नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि जो स्पेशल एक्ससाइज ड्यूटी और एडिशनल एक्ससाइज ड्यूटी लगाई गई है उसमें भी राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि केंद्र सरकार कम से कम 10 रुपये पेट्रोल पर और 15 रुपये डीजल पर कम करे। गहलोत ने यह कि केंद्र सरकार साल 2022 तक जो जीएसटी का पुनर्भरण कर रही थी उसे साल 2027 तक आगे बढ़ाए। साथ ही राजस्थान को बकाया 5900 करोड़ रुपये जीएसटी पुनर्भरण का भुगतान जल्द करे।

गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि बीते 7 सालों में महंगाई आसमान छूने लगी है और पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने की चीजें तक महंगी हुई हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया इस दौरान यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री की कीमतों की तुलना आज चल रही कीमतों से की।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिफॉर्म बाजी छोड़ परीक्षा की तैयारी करने की नसीहत दी है ताकि उनकी नौकरी लग सके। गहलोत ने कहा कि युवाओं को विपक्ष वाले भड़का रहे हैं जिसके चलते वे राजनीतिक दलों के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर

विरोध प्रदर्शन कर रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार दिया गया है। एक लाख नौकरियां तो दी जा चुकी हैं और 75 हजार नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। ऐसे में जो युवा यूनिफॉर्म बाजी में लगे हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि उनकी नौकरियां लग सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जो नौकरियां राजस्थान में निकली हुई हैं, अधिकतर युवा तो उनकी तैयारी में लगे हैं लेकिन कुछ यूनिफॉर्म बाजी में जुटे हैं। उनमें कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी लग भी जाए तो वह ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वह नेतागिरी करके इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं। चाहे बीजेपी और कांग्रेस उन्हें टिकट क्यों न दे दे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इन युवाओं को भड़काने का काम विपक्ष के रूप में भाजपा कर रही है। राजस्थान में हुए उपचुनाव में भाजपा की जो दुर्गति हुई है, उसके बाद यहां के नेता केवल इसी मिशन पर जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरह पद पर बने रहें, क्योंकि आलाकमान हटा देगा और इसी के चलते युवाओं को भड़काने का काम चल रहा है।

हाईटेंशन लाइन से प्रभावित भूखंडों के पट्टे देने की मांग

जयपुर। राजधानी के पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन से प्रभावित भूखंडों के पट्टों की मांग लगातार जारी है। रविवार को पृथ्वीराज नगर हाईटेंशन लाइन संघर्ष समिति ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खारचियावास को ज्ञापन दिया।

समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जो 2015 में नए नियम बनाए गए हैं, उनसे पृथ्वीराज नगर को बाहर रखा जाए क्योंकि यहां की कॉलोनियां 30 से 40 वर्ष पुरानी हैं। 60 फीट रोड पर पट्टे दिलवाने की मांग की। इस मौके पर अनिल माथुर, दिनेश राव, ओम प्रकाश जाखड़, नवीन श्रीवास्तव, चेतन धलवानी, हनुमान सिंह मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2015 में नगरीय विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें 132 केवी और 220 केवी की हाईटेंशन लाइनों के नीचे 105 फीट और 120 फीट पर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से पीआरएन में 20 हजार से अधिक भूखंडधारियों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं।

चाकू से गला रेतकर मजदूर की हत्या करने वाले तीन गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मजदूर की हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। डीसीपी (वेस्ट) ऋचा तोमर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित लीलाराम मीणा (36), संतोष मीणा उर्फ संतराम (45) और गंगा लहरी (35) थाना प्रतापगढ़, धानागाजी (अलवर) के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 26 नवंबर को अपने साथी मजदूर जयनारायण उर्फ जैनी मीणा की चाकू से गला काटकर नृशंश हत्या कर दी थी।

थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि मृतक जयनारायण उर्फ जैनी और उसके साथी मजदूर लीलाराम मीणा, गंगालहरी उर्फ लहरी मीणा, संतोष उर्फ संतराम मीणा एक ही फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। खाना बनाने की बात को लेकर अक्सर इनके बीच आपस में लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी मृतक जयनारायण का साथी मजदूरों से खाना बनाने, आटा लगाने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। मृतक ने खाना

- **खाना बनाने समय गाली-गालीच करने पर साथी मजदूरों ने की थी हत्या**
- **वीकेआई पुलिस ने 24 घंटे में वारदात का खुलासा कर बदमाशों को पकड़ा**

बनाने से इंकार कर दिया और साथी मजदूरों को गन्दी-गन्दी गलियां दी। इस पर साथी मजदूर आक्रोशित हो गए और जयनारायण मीणा को मारने का प्लान बनाया। जयनारायण मीणा लघुशंका के लिए गटर की तरफ जाने लगा तो दो मजदूरों ने जयनारायण को पकड़ लिया और तीसरे मजदूर ने चाकू से गला रेत दिया। काफी खून बहने से उसकी मौत हो गयी। आरोपी मजदूरों ने लाश को उठाकर दूसरी जगह पर फिर्त करके में लाकर फर्श पर लिटा दी। मौके से साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गए थे।

सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के असंवैधानिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री को यू-टर्न लेना पड़ रहा है : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह स्वीकारोक्ति करना कि सलाहकार एवं संसदीय सचिवों को राज्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है एवं सरकार ने इसके लिए कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किए हैं, इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने महज असंतुष्ट कांग्रेस व अन्य समर्थित विधायकों को खुश करने एवं अंतर्कलह से जुझती अपनी सरकार को बचाने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की है। वास्तविकता में नियुक्त सलाहकार महज सामान्य विधायक के कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे।

- **‘मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त सलाहकार केवल नाम मात्र के होंगे, सलाहकारों के पास लेटर पैड पर अपना नाम/पद अंकित करने के अलावा कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं होंगी’**
- **‘राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के बाद अब सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने का साहस नहीं जुटा पा रही है’**

अधिकारिता में नहीं हैं। धारा 5 (2) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति/अधिकारी ऐसी गोपनीय सूचना को अपने पास रखता है जिसकी उसकी कोई अधिकारिता नहीं है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा। ऐसे दोषी व्यक्ति/अधिकारी को 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकारोक्ति करने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि उनके द्वारा नियुक्त सलाहकार के पास सरकार द्वारा कोई पत्रावली नहीं भेजी जा सकती है और ना ही उनकी सलाह पर कोई पत्रावली चलाई जा सकती है। यह महज विधायकों को खुश करने के लिए

खुनझुना देना है। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त सलाहकार केवल नाम मात्र के होंगे, सलाहकारों के पास लेटर पैड पर अपना नाम/पद अंकित करने के अलावा कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं होंगी। सामान्य विधायक के अतिरिक्त इन सलाहकारों के पास कोई संवैधानिक अधिकार भी नहीं होंगे। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सलाहकारों की असंवैधानिक नियुक्ति व संसदीय सचिवों की संभावित नियुक्ति को लेकर मैंने 22 नवंबर को राज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के बाद से अब सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के असंवैधानिक फैसले के

बाद मुख्यमंत्री को यू-टर्न लेना पड़ रहा है और वह सलाहकारों को राज्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाओं के लिए लिखित आदेश भी जारी नहीं कर पा रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही 6 सलाहकारों के कर्तव्य पद गई और उन्हें सलाहकार के पद का झुनझुना पकड़ना दिया। मुख्यमंत्री की बताना चाहिए कि क्या कांग्रेसी सचिवों की पार्टी में सम्मानजनक स्थिति नहीं थी या फिर क्या विधायक का पद कम महत्वपूर्ण है? जो उन्हें सलाहकार जैसे पद की रेवडियां बांटनी पड़ रही है।

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि सलाहकारों की नियुक्तियों के मामले को लेकर विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है और सरकार को तामा कानूनों की पूरी जानकारी है। हकीकत तो यह है कि अगर सरकार को संवैधानिक प्रावधानों की पूरी जानकारी होती तो आज मुख्यमंत्रीजी को लोकतंत्र का उपहास करते हुए एवं आपसी कलह की नियुक्ति करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। सलाहकार के पद पर नियुक्ति देने की जरूरत ही नहीं होती।

गांधीजी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी : मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सेन्ट्रल पार्क में बन रहे गांधी दर्शन म्यूजियम के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटसरा और जेडीसी गौरव गोयल भी मौजूद थे।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुल्क में प्रेम, भाईचारा एवं सद्भाव कायम करने के लिए आज गांधीजी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गांधी दर्शन एवं गांधीजी की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार जिला, ब्लॉक एवं गांव के स्तर तक हो।

गहलोत रविवार को सेन्ट्रल पार्क स्थित कनक भवन में आयोजित गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधी दर्शन को युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने गांधीजी के विचारों को आमजन तक पहुंचाने के लिए अलग से निदेशालय

बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीजी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए प्रशासन एवं सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से मुम्बई के टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड स्कुल ऑफ गवर्नंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नंस एण्ड सोशल साइंसेज की स्थापना की गई है। यहां गांधीजी से जुड़े शोध कार्य होंगे। उन्होंने गांधीजी के विचारों के प्रचार-प्रसार की दिशा में गांधी दर्शन समिति द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नंस एण्ड सोशल

साइंसेज के निदेशक प्रो. बीएम शर्मा, शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष शर्मा, समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सिद्धांत सिंह, गांधी स्मरक निधि के सदस्य धर्मवीर कटेवा, वर्षा आश्रम से आए मुख्य प्रशिक्षक मनोज नागरे एवं आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सेन्ट्रल पार्क में बन रहे गांधी दर्शन म्यूजियम के कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूरे करने के निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल ने साइट प्लान के बारे में जानकारी दी। गहलोत ने वहां मौजूद कामगारों से बातचीत की और उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी।

जेकेके में पुस्तक प्रेमियों ने अपनी चुनौतियां और अनुभव साझा किए

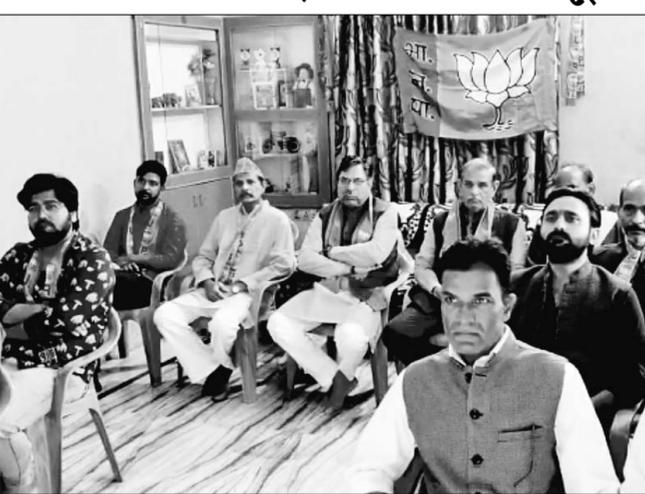
जयपुर, (का.सं.)। जवाहर कला केंद्र (जेकेके) और जयपुर बुक लवर्स की ओर से रविवार को बुक्स विच हैव चैलेंज/एक्सपैड/चेंज/योर पर्सपेक्टिव विषय पर चर्चा करने और अपने विचारों को साझा करने के लिए जयपुर के पुस्तक प्रेमियों के लिए जेकेके लाइब्रेरी में मीट अप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का संचालन वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट अजय अस्वाल, विवेक शर्मा और प्रशांत गुप्ता ने किया। इस सेशन में 14 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के करीब 25 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेट, नए लेखकों सहित स्कूली बच्चों ने भी बह चर्चा कर हिस्सा लिया।

इस इंटरैक्टिव सेशन में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लेखकों की पुस्तकों जैसे कि युवाल नोआ ह्यारी की सेपियंस, सिद्धार्थ मुखर्जी की द जीन, द फाउंटैन हेड सहित कई अन्य पुस्तकों पर चर्चा की और अपने विचार रखे। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने पुस्तकें पढ़ ना शुरू किया।

ठेकेदार ने महिला से किया दुष्कर्म

जयपुर (कासं)। भांकोटा इलाके में एक ठेकेदार द्वारा महिला मजदूर से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार झोटवाड़ा इलाके निवासी 28 वर्षीया महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह 17 नवंबर को सिरसी में एक शादी में काम करने गई थी। महिला का आरोप है कि चापिसी में लौटते वक्त ठेकेदार मकखन लाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जांच में जुटी है।

‘मन की बात’ कार्यक्रम देश के लोगों को जोड़ता है : डॉ. पूनिया



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने जयपुर के करणी विहार मण्डल में बृथ नंबर 316 पर कार्यकर्ता के घर पर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने जयपुर के करणी विहार मण्डल में बृथ नंबर 316 पर कार्यकर्ता के घर कार्यकर्ताओं के साथ सुना।

डॉ. पूनिया ने पार्टी के प्रदेशभर के सभी बृथ अध्यक्षों से आग्रह करते हुये कहा कि, मन की बात कार्यक्रम को सुनने में निरंतरता लाएं और मन की बात देश के लोगों को जोड़ता है और मकसद के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने सबसे मन को छुआ।

- **‘प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट-अप की अभिनव पहल से देश एवं प्रदेश के नौजवानों को जाँब क्रिएटर्स के रूप में नई दिशा दी’**

जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात अब मकसद की बात होती जा रही है। खास तौर पर आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धियां और मधुरा की सुखदेवी के मुख से जब आयुष्मान की अहमियत समझी, तो उस बात ने भावुक

हड़ताल से बिगाड़ी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था

जयपुर। शहर में हूपर संचालकों की पिछले तीन दिनों से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। अब सोमवार से एक बार फिर सफाई व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। तीन दिन की हड़ताल के चलते शहर में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक कि बकाया भुगतान की मांग को लेकर ये वैडस हड़ताल पर थे। बीबीजी कंपनी के साथ कई बाद की बातों भी हुईं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं होने से हूपर चालक काम पर नहीं लौटे। ग्रेटर निगम में 7 और हैरिटेज के दो जोन में काम बंद पड़ा था। निगम के हस्तक्षेप के बाद वैडस को कंपनी ने समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। इस हड़ताल की वजह से शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। परकोटा क्षेत्र, जगतपुरा, सिविल लाइंस, मालवीय नगर समेत कई वीआईपी इलाकों में भी कचरा नहीं उठा है।

मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने रविवार को श्रीरामचन्द्रजी मन्दिर, सिरह ड्योड़ी बाजार में विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रावत ने ऐसे अराजकीय मंदिर जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिए जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश

दिए। साथ ही, नियमित पूजा से वंचित मंदिरों को ट्रस्टों, उद्योगों एवं मंदिरों में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को गोद दिए जाने के लिए एक स्थाई नीति बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंदिर सेवा पूजा से वंचित नहीं रहना चाहिए। शासन सचिव देवस्थान सौभाग्य भाले ने विभागीय नीतियों और उनकी क्रियान्विति से अवगत

कराते हुए बताया कि विभाग की ओर से मंदिरों का नियमित निरीक्षण कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर आयुक्त करण सिंह, संयुक्त शासन सचिव अजय सिंह राठौड़, उपायुक्त सुनील मत्तड़ एवं सहायक आयुक्त आकाश रंजन और महेंद्र कुमार देवतवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।